नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 133
दि. 15.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

ब्रह्मपुत्र के गर्भ में बनेगी भारत की पहली रेल रोड सुरंग, पूर्वोत्तर में विकास की नई धड़कन

(जीएनएस)। भारत की आधारभूत संरचना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने असम में बहने वाली महान ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडरवॉटर सड़क-सह-रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण होगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक निर्णायक कदम भी साबित होगी। इस सुरंग के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी और यात्रा समय में ऐतिहासिक कमी आएगी और क्षेत्र के लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह परियोजना अब वास्तविक रूप लेने की दिशा में बढ़ चुकी है। यह सुरंग असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच बनने वाले 33.7 किलोमीटर लंबे चार-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा होगी। इस पूरे कॉरिडोर में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे लगभग 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग बनाई जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 18,662 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और इसे इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह भारत की पहली ऐसी सुरंग होगी जिसमें एक ही संरचना के भीतर सड़क और रेलवे दोनों की सुविधा होगी, जो इसे तकनीकी और संरचनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

वर्तमान में गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा करने के लिए लोगों को लगभग 240 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जो कालियाभम्भोरा पुल और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से होकर गुजरता है। इस मार्ग से यात्रा करने में लगभग छह घंटे का समय लगता है। लेकिन नई सुरंग के निर्माण के बाद यह दूरी घटकर मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा का समय केवल 20 से 30 मिनट तक सीमित हो जाएगा। यह परिवर्तन न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि ईंधन की खपत, परिवहन लागत और यात्रा की असुविधाओं को भी काफी हद तक कम कर देगा।

इस सुरंग की सबसे बड़ी विशेषता इसका मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। इसमें दो अलग-अलग ट्यूब बनाई जाएंगी, जिनमें से एक ट्यूब में चार-लेन सड़क होगी, जबकि दूसरी ट्यूब रेलवे ट्रैक के लिए

निर्धारित होगी। इसका मतलब यह है कि इस सुरंग के भीतर से एक ही समय में ट्रेन और वाहन दोनों गुजर सकेंगे। यह सुविधा भारत के परिवहन नेटवर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन करेगी।

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मिलेगा। असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और आसपास के अन्य राज्यों को इसका सीधा फायदा होगा। इन राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में जो भौगोलिक बाधाएं थीं, वे काफी हद तक दूर हो जाएंगी। इससे न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

इस सुरंग के निर्माण से माल ढुलाई की प्रक्रिया अधिक तेज और कुशल हो जाएगी। वर्तमान में लंबी दूरी और कठिन मार्गों के कारण परिवहन लागत अधिक होती है और समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन सुरंग बनने के बाद माल और संसाधनों का परिवहन तेज गति से हो सकेगा, जिससे उद्योगों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

रणनीतिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण वहां मजबूत और तेज कनेक्टिविटी की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह सुरंग सीमा क्षेत्रों तक पहुंच को आसान बनाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह परियोजना केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी नई मजबूती प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से जोड़ना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

पर्यटन के क्षेत्र में भी इस परियोजना का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे स्थानीय व्यवसायों, होटल उद्योग और पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

इस परियोजना के निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। अनुमान है कि इसके निर्माण के दौरान लगभग 80 लाख मानव-दिवसों का रोजगार सृजित होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। निर्माण कार्य में इंजीनियरों, तकनीशियनों, मजदूरों और अन्य विशेषज्ञों की बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी, जिससे कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

सड़कों के गड्ढे बन रहे जानलेवा जाल, पांच साल में मौतों में 53 फीसदी का चिंताजनक उछाल

(जीएनएस)। देश में सड़कें विकास और प्रगति की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन जब यही सड़कें गड्ढों से भर जाती हैं तो वे लोगों के लिए मौत का कारण बन जाती हैं। हाल ही में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों ने एक बेहद चिंताजनक सच्चाई उजागर की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में सड़कों पर मौजूद गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या पिछले पांच वर्षों में 53 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुल 9,438 लोगों ने केवल सड़क के गड्ढों की वजह से अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा न केवल देश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि बुनियादी ढांचे की खामियां किस तरह लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं।

इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2020 में गड्ढों के कारण 1,555 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में यह संख्या थोड़ी घटकर 1,481 हो गई, जिससे यह उम्मीद जगी कि स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन यह राहत अस्थायी साबित हुई। वर्ष 2022 में मौतों की संख्या बढ़कर 1,856 हो गई, वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 2,161 तक पहुंच गया और वर्ष 2024 में यह बढ़कर 2,385 हो गया। इस तरह लगातार तीन वर्षों तक मौतों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय है।

राज्यों के आधार पर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे अधिक प्रभावित राज्य के रूप में सामने आया है। इस अवधि में देश में हुई कुल मौतों में से 54 प्रतिशत से अधिक मौतें केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं। पांच वर्षों में राज्य में कुल 5,127 लोगों की जान गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं में गई। केवल वर्ष 2024 में ही राज्य में 1,369 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो देश के कुल आंकड़े का आधे से भी अधिक हिस्सा है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य में सड़क रखरखाव और सुरक्षा उपायों में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। अन्य राज्यों में भी स्थिति चिंताजनक रही है। मध्य प्रदेश में इस अवधि के दौरान 969 मौतें दर्ज की गईं, जबकि तमिलनाडु में 612 और पंजाब में 414 लोगों की जान गई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि समस्या केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में फैली हुई है। हालांकि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा में इस अवधि के दौरान गड्ढों के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई, जो यह संकेत देता है कि यदि सड़क रखरखाव और निगरानी की व्यवस्था मजबूत हो, तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का प्रभाव केवल मौतों तक सीमित नहीं है। इन पांच वर्षों में देशभर में कुल 23,056 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 19,956 लोग घायल हुए। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। दुर्घटना के बाद लंबे समय तक इलाज, आर्थिक नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है, जिससे पीड़ित और उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

सड़क विशेषज्ञों का मानना है कि गड्ढों की समस्या मुख्य रूप से खराब निर्माण गुणवत्ता, समय पर मरम्मत न होना, भारी बारिश, जल निकासी की खराब व्यवस्था और निगरानी की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जब सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जाता या समय पर मरम्मत नहीं होती, तो सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं और गड्ढे बन जाते हैं। बारिश के दौरान पानी गड्ढों में भर जाता है, जिससे वे दिखाई नहीं देते और वाहन चालक अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

इस गंभीर समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने सड़क रखरखाव और मरम्मत के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही है। मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, जबकि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव के लिए जवाबदेह एजेंसियों के माध्यम से समय पर मरम्मत और निगरानी की व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़कें सुरक्षित और सुगम बनी रहें।

सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया है। सड़कों की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम, ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खराब सड़कों की पहचान जल्दी हो सके और समय पर मरम्मत की जा सके। इसके अलावा, ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

रिटायर अफसरों की किताबों पर लग सकती है 20 साल की रोक, सरकार के प्रस्ताव से बढ़ी बहस

(जीएनएस)। देश की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार रिटायरमेंट के बाद उच्च पदों पर रहे अधिकारियों के लिए 20 साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी अपनी सेवा से जुड़े अनुभवों, घटनाओं या संवेदनशील जानकारियों पर आधारित कोई भी किताब या प्रकाशन इस अवधि के दौरान जारी नहीं कर सकेंगे। इस संभावित फैसले ने प्रशासनिक हलकों, सैन्य समुदाय और नीति विशेषज्ञों के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। यह मुद्दा हाल ही में तब चर्चा में आया जब भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक को लेकर विवाद सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार, उनकी पुस्तक में कुछ ऐसे सैन्य और रणनीतिक पहलुओं का उल्लेख किया गया था, जिन्हें संवेदनशील माना गया। इस घटना के बाद सरकार के भीतर यह विचार तेज हुआ कि उच्च पदों पर रहे अधिकारियों द्वारा सेवा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से पहले एक स्पष्ट और सख्त नीति बनाई जानी चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। हालांकि यह मुद्दा कैबिनेट के आधिकारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं था, लेकिन सामान्य चर्चा के दौरान कई मंत्रियों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। मंत्रियों का मानना था कि सेना, खुफिया एजेंसियों, विदेश सेवा और अन्य संवेदनशील पदों पर रहे अधिकारियों के पास ऐसी गोपनीय जानकारियां होती हैं, जिनका सार्वजनिक होना देश की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए, रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित अवधि तक ऐसे अधिकारियों के प्रकाशनों पर प्रतिबंध आवश्यक हो सकता है।

प्रस्तावित कूलिंग-ऑफ पीरियड का उद्देश्य केवल प्रकाशनों को रोकना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करना भी है। वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णयों, रणनीतियों और संवेदनशील ऑपरेशनों का हिस्सा होते हैं। यदि ये जानकारियां बिना उचित अनुमति के सार्वजनिक हो जाती हैं, तो इससे न केवल देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार के इस संभावित कदम को कुछ विशेषज्ञ राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक मान रहे हैं। उनका कहना है कि कई देशों में भी इस तरह के नियम मौजूद हैं, जहां संवेदनशील पदों पर रहे अधिकारियों को सेवा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से पहले अनुमति लेनी होती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो, जो देश के हितों के खिलाफ हो।

हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है। उनका मानना है कि 20 साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड बहुत लंबा हो सकता है और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। कई सेवानिवृत्त अधिकारी अपने अनुभवों को साझा करके देश के प्रशासनिक और सैन्य इतिहास को समृद्ध करते हैं। उनकी किताबें न केवल ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सीख का स्रोत भी बनती हैं। ऐसे में लंबी अवधि तक प्रकाशन पर रोक लगाने से महत्वपूर्ण अनुभव और ज्ञान सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे।

कुछ पूर्व अधिकारियों का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय एक संतुलित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें प्रकाशन से पहले संबंधित विभाग या सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य हो।

चुनाव से पहले असम पुलिस में बड़ा फेरबदल, मुख्यमंत्री के भाई सुशांत विश्व शर्मा बने सीआईडी के सीनियर एसएसपी

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य असम में विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। इस बदलाव के तहत मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के भाई और बरपेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे सुशांत विश्व शर्मा का तबादला कर उन्हें अपराध जांच विभाग (सीआईडी) में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का सीनियर एसएसपी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं और प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।

सुशांत विश्व शर्मा की नई जिम्मेदारी को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण होती है। सीआईडी की यह शाखा राज्य में होने वाले गंभीर अपराधों की जांच करती है और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इस पद पर उनकी नियुक्ति प्रशासन की रणनीतिक प्राथमिकताओं को भी दर्शाती है।

बरपेटा जिले में उनके स्थान पर अब पुष्किन जैन को नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। वहीं, गुवाहाटी में भी पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गुवाहाटी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस) हरेकृष्ण नाथ को सीआईडी के व्हाइट कॉलर क्राइम विंग का एसएसपी बनाया गया है। उनकी जगह हिरण्य कुमार बर्मन

को नया डीसीपी (इंटेलिजेंस) नियुक्त किया गया है। यह बदलाव राज्य में आर्थिक अपराधों और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है।

इसके अलावा, अन्य कई जिलों और पुलिस इकाइयों में भी अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। बसिष्ठ के सहायक पुलिस आयुक्त प्रांजल बरुआ को सादिया का नया डीएसपी बनाया गया है, जबकि एसटीएफ के डीएसपी सत्येंद्र सिंह हजारी को बसिष्ठ का नया सहायक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। सादिया के डीएसपी नैमुद्दीन को चराइदेव जिले में डीएसपी (सिक्योरिटी) के पद पर भेजा गया है। वहीं, चराइदेव के मौजूदा अधिकारी मृणाल कुमार दास को भी सुरक्षा से जुड़ी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विजिलेंस और एंटी-करप्शन विभाग के डीएसपी ऋतुपर्ण गोगोई को तिनसुकिया जिले का डीएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि उनकी जगह अमर ज्योति सैकिया को विजिलेंस और एंटी-करप्शन विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी तबादलों और नियुक्तियों का आदेश गृह और राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय तिवारी द्वारा जारी किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आगामी चुनावों से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के प्रशासनिक बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना एक रणनीतिक कदम माना जाता है।

असम में विधानसभा चुनाव मार्च या अप्रैल 2026 में होने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है। राज्य की राजनीति में यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होगी। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में हुए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। 2021 के चुनावों में भाजपा ने 60 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह एनडीए गठबंधन को कुल 75 सीटें मिली थीं, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन को कुल 50 सीटें मिली थीं, जिसमें कांग्रेस ने 29 और एआईयूडीएफ ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी।

असम में पुलिस विभाग में किए गए ये हालिया बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यह फेरबदल न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है, बल्कि आगामी चुनावों के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नियुक्तियों और प्रशासनिक बदलावों का राज्य की कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है।

संपादकीय

देशव्यापी साजिशों का हो पर्दाफाश

पिछले दिनों दिल्ली में अप्रत्याशित रूप से लोगों की गुमशुदगी की घटनाओं ने नीति-नियंताओं व अदालतों समेत पूरे देश का ध्यान खींचा। इस मामले में संज्ञान लेते हुए देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस बात की जांच करने के निर्देश दिए कि देश के विभिन्न इलाकों में बच्चों की लगातार लापता होने की घटनाओं में कहीं किसी देशव्यापी गिरोहों का हाथ तो नहीं है? संकट कितना बड़ा है यह इस बात से पता चलता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में सारे देश से करीब आठ लाख लोग लापता हुए हैं, जिनमें अधिकांशतः बच्चे, महिलाएं और लड़कियां शामिल रही हैं। जाहिर तौर पर लापता लोगों का बढ़ता आंकड़ा कहीं न कहीं तंत्र की लापरवाही को ही उजागर करता है, जिसके चलते अपराधी-तत्व अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। इसी साल जनवरी के पहले पखवाड़े में सिर्फ दिल्ली से आठ सौ लोगों के लापता होने की खबरों ने देशवासियों की चिंताओं को बढ़ाया है। देशवासियों में इस बात को लेकर भी चिंता और नाराजगी है कि इस गंभीर आपराधिक संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वय से कोई व्यापक अभियान क्यों नहीं चलाया जाता। विडंबना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि राज्यवार कितने लोग वापस लौटे हैं और कितने लोग अभी भी गायब हैं। निश्चित रूप से इस संकट से निपटने के लिए एकीकृत राज्यवार ब्योरा उपलब्ध कराने की जरूरत है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि राज्यों से लापता बच्चों और उनसे जुड़े अभियोजन के अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दरअसल, यह पहली बार नहीं है कि शीर्ष अदालत ने लापता बच्चों के आंकड़े जुटाने को कहा हो। कोर्ट ने बीते साल दिसंबर में भी केंद्र सरकार से लापता बच्चों से जुड़े पिछले छह साल के देशव्यापी आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा था।

दरअसल, कोर्ट ने इस बाबत राज्य के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करके प्रामाणिक जानकारी जुटाने को कहा था। इतना ही नहीं, गुमशुदा बच्चों की तलाश के मामले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के भी निर्देश दिए गए थे। इस दिशा में अपेक्षित प्रगति का न होना हमारे तंत्र की व्यवस्थागत कमियों को ही उजागर करता है। निर्विवाद रूप से सारे देश से यदि लाखों लोगों के लापता होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो बहुत संभव है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा होगा। साथ ही यह भी पता लगाने की जरूरत है कि लापता लोगों के मामले में अपराधियों की कारगुजारियों में कहीं एकरूपता तो नहीं है। विगत में मानव तस्करी के मामले गाहे-बगाहे उजागर होते रहे हैं, जिसमें लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेलने के भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस संकट का समाधान तभी संभव होगा जब देश के सभी राज्यों से प्रामाणिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। उनके व्यापक अध्ययन से अपराध करने की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। इसके साथ ही जरूरी है कि राज्य सरकारें भी अपने दायित्व को गंभीरता से निभाएं। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त न की जाए। इसके अलावा निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। देश की कानून-व्यवस्था में भरोसा कायम करने के लिए इन घटनाओं को शासन-प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से लिया जाना भी जरूरी है। यहां इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की तरफ से राज्यों में बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़े दर्ज करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, उसमें नियमित रूप से आंकड़े क्यों नहीं दर्ज किए जाते हैं। यह विडंबना है कि सरकारों को जिस दायित्व को अपने स्तर पर ईमानदारी से निभाने की जरूरत होती है, उसके लिये देश की शीर्ष अदालत को बार-बार याद दिलाना पड़ता है। नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी सुरक्षा गाइड लाइन्स जारी करने की जरूरत है, जिससे लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए सजग व सतर्क रह सकें।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की वैचारिक क्रांति

> “ बांग्लादेश के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्या वह अपनी पहचान को केवल धार्मिक राष्ट्रवाद तक सीमित करेगा, या भाषा, संस्कृति और बहुलता की उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसने उसे जन्म दिया? मुक्ति संग्राम की मूल भावना सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी।

बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ी है। लगभग दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंचते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा परिवर्तन का संकेत होगा। 299 सीटों में से 212 पर विजय का दावा इस बात का प्रमाण है कि मतदाता लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता, अंतरिम व्यवस्थाओं और वैचारिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलकर एक निर्णायक जनादेश देना चाहता है। छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी का मात्र छह सीटों पर सिमटना भी इस तथ्य को पुष्ट करता है कि जनभावना प्रयोगधर्मिता से आगे बढ़कर स्थायित्व की ओर झुक रही है। लगभग अठारह महीने से चल रही अंतरिम व्यवस्था के अवसान के साथ बांग्लादेश एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है, पर प्रश्न यह है कि यह अध्याय उदार लोकतंत्र का होगा या किसी नए प्रकार के वैचारिक वर्चस्व का? बांग्लादेश का इतिहास संघर्ष, त्याग और पहचान की जिजीविषा से निर्मित हुआ है। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका केवल सैन्य सहायता तक सीमित नहीं थी, वह सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग का भी प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक धुरवीकरण, कट्टरवादी विमर्श और बाहरी प्रभावों ने उस ऐतिहासिक आत्मीयता पर धुंध डालने का प्रयास किया। अंतरिम सरकार के दौरान जिस प्रकार वैचारिक कठोरता और प्रशासनिक असमंजस दिखा, उसने अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने दोनों को प्रभावित किया। ऐसे समय में स्पष्ट जनादेश को स्थिरता का अवसर माना जा सकता है, बशर्ते सत्ता इसे प्रतिशोध का माध्यम न बनाए, बल्कि पुनर्निर्माण का औजार बनाए।

तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना होगी। बांग्लादेश का सामाजिक ढांचा बहुलतावादी है, वहां अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और सम्मान केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की कसौटी है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से दूरी बनाकर विकासोन्मुखी एजेंडा अपनाती है, तो वह न केवल आंतरिक स्थिरता ला सकती है, बल्कि दक्षिण एशिया में एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकती है। पर यदि चुनावी विजय को वैचारिक वर्चस्व के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो यह जनादेश अवसर से अधिक संकट में बदल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वस्त्र उद्योग, निर्यात वृद्धि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उसने मिसाल कायम की। किंतु राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने निवेशकों के विश्वास को झटका दिया। अब नई सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह आर्थिक सुधारों को गति दे, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करे और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाए। विकास की “नई गंगा” तभी बहेगी जब शासन पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी होगा। केवल नारे या राष्ट्रवाद की तीखी ध्वनियां आर्थिक संकट का समाधान नहीं बन सकतीं। भारत-बांग्लादेश संबंध इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता और आर्थिक परस्परता है। सीमा प्रबंधन, जल बंटवारा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे परस्पर विश्वास से ही सुलझ सकते हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती निकटता और भारत के प्रति संदेहपूर्ण बयानबाजी ने संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा किया। यदि नई सरकार क्षेत्रीय संतुलन की नीति अपनाते हुए भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद पुनः स्थापित करती है, तो यह दोनों देशों के हित में होगा। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस ऐतिहासिक साझेदारी को भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक आधार पर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब केवल द्विपक्षीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। चीन की बढ़ती उपस्थिति, अमेरिका की रणनीतिक रुचि और पाकिस्तान की पारंपरिक भूमिका-इन सबके बीच बांग्लादेश को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी। यदि नई सरकार वैचारिक आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखती है, तो वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक परिपक्व भूमिका निभा सकती है। परंतु यदि विदेश नीति घरेलू राजनीति का विस्तार बन गई, तो अस्थिरता का चक्र फिर दोहराया जा सकता है। इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बांग्लादेश का मतदाता अब निर्णायकता चाहता है। लंबे समय तक आंदोलन, विरोध और अंतरिम प्रयोगों से थका समाज स्थिर शासन की आकांक्षा रखता है। किंतु स्थिरता केवल बहुमत से नहीं आतीय वह संस्थाओं की मजबूती, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वायत्तता से आती है। नई सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने की संस्कृति का नाम है। यदि विपक्ष को हाशिये पर धकेला गया या आलोचना को देशविरोध का रूप दिया गया, तो लोकतांत्रिक ऊर्जा क्षीण हो जाएगी।

बांग्लादेश के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्या वह अपनी पहचान को केवल धार्मिक राष्ट्रवाद तक सीमित करेगा, या भाषा, संस्कृति और बहुलता की उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसने उसे जन्म दिया? मुक्ति संग्राम की मूल भावना सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी। यदि नई सत्ता उस भावना को पुनर्जीवित करती है, तो यह जनादेश ऐतिहासिक सिद्ध होगा। अन्यथा यह अवसर भी इतिहास की एक और चूकी हुई संभावना बन सकता है।

भारत की दृष्टि से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली को प्रतिक्रिया में उतावलापन नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीतिक परिपक्वता दिखानी होगी। पड़ोसी देश की संप्रभुता और जनादेश का सम्मान करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाना ही दीर्घकालिक हित में है। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर सख्ती के साथ-साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संवाद को भी सुदृढ़ करना होगा। संबंधों में भावनात्मकता के बजाय व्यावहारिकता और पारस्परिक सम्मान की नींव आवश्यक है।

अंततः यह चुनाव बांग्लादेश के लिए निर्णायक इसलिए है क्योंकि यह केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं, बल्कि शासन की शैली और राष्ट्रीय दिशा तय करने का क्षण है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से मुक्त, समावेशी और विकासोन्मुखी नीति अपनाती है, तो वह बांग्लादेश को स्थिरता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर सकती है। परंतु यदि वह अतीत की कटु स्मृतियों और वैचारिक आग्रहों में उलझी रही, तो जनादेश की सार्थकता संदिग्ध हो जाएगी। बांग्लादेश को अब नई संभावनाओं, नई सोच और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। यही इस चुनाव का संदेश है और यही उसकी वास्तविक परीक्षा भी।

प्रेरणा

रस का रहस्यः जब मन तृप्त होता है, वही सर्वोत्तम भोजन बन जाता है

मानव जीवन में अनुभवों का महत्व शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। जो बात पुस्तकों से नहीं सीखी जा सकती, वह एक साधारण अनुभव से समझ में आ जाती है। ऐसा ही एक अद्भुत अनुभव विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवन में तब आया, जब वे आध्यात्मिक शांति और प्रकृति की गोद में स्वयं को खोजने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकले। हिमालय केवल पर्वतों का समूह नहीं है, बल्कि वह आत्मा की शुद्धि का स्थान है, जहाँ मनुष्य अपने भीतर छिपे सत्य से साक्षात्कार करता है। गुरुदेव का हृदय प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। जब वे ऊँचे-ऊँचे पर्वतों, शीतल हवाओं और शांत वातावरण के बीच पहुँचे, तो उनका मन स्वतः ही संगीत में डूब गया। वे चलते-चलते गीत गाने लगते, मानो उनके भीतर से कोई दिव्य स्वर निकल रहा हो। जब वे केदारनाथ मंदिर के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ता कठिन और थकाने वाला था। ऊँचाई, ठंड और लंबी यात्रा ने शरीर को थका दिया था, लेकिन आत्मा अभी भी उत्साह से भरी हुई थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया, जो साधारण था, लेकिन उस समय वही उनके लिए विश्राम का स्थान बन गया। उनके साथ जो सहयोगी थे, वे जानते थे कि गुरुदेव को खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी उनके लिए केवल भोजन नहीं, बल्कि एक प्रिय स्वाद था, जो उन्हें संतोष देता था। लेकिन उस ढाबे में खिचड़ी उपलब्ध नहीं थी। वहाँ केवल भुने हुए आलू और हरा नमक ही था, जिसे एक साधारण हरे पत्ते में परोसा गया। यह दृश्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए निराशाजनक हो सकता था। लंबी यात्रा के बाद, जब शरीर थका हुआ हो और मन किसी विशेष भोजन की अपेक्षा कर रहा हो, तब साधारण भोजन मिलने पर असंतोष होना स्वाभाविक है। लेकिन गुरुदेव ने उस भोजन को जिस भाव से स्वीकार किया, वह असाधारण था। उन्होंने उस भुने हुए आलू को इतने प्रेम और आनंद के साथ खाना शुरू किया, मानो वह कोई दुर्लभ और अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन हो। उनके चेहरे पर संतोष की एक गहरी मुस्कान थी। वे हर कौर को ध्यानपूर्वक और आनंद के साथ ग्रहण कर रहे थे। उनके सहयोगी यह देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने उस क्षण की पवित्रता को भंग करना उचित नहीं समझा।

यह केवल भोजन करने का कार्य नहीं था, बल्कि वह एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी। गुरुदेव उस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित थे। उनका मन न तो अतीत की किसी स्मृति में था और न ही भविष्य की किसी अपेक्षा में। वे केवल वर्तमान में थे, और उसी वर्तमान में उन्हें पूर्ण संतोष प्राप्त हो रहा था। यही संतोष जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मनुष्य वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तब साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं।

कुछ समय बाद जब वे फिर से यात्रा पर आगे बढ़े, तो उनके एक सहयोगी ने संकोचपूर्वक उनसे पूछा, “गुरुदेव, क्या सच में वह भुना हुआ आलू आपको इतना स्वादिष्ट लगा?” यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि वह उस अनुभव के रहस्य को समझने का प्रयास था। गुरुदेव ने शांत और संतोषपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, “स्वाद और जायके का कोई अलग या स्थायी रूप नहीं होता। स्वाद केवल भोजन में नहीं होता, वह हमारे मन में होता है। जब हमारा मन संतुष्ट होता है, तो साधारण भोजन भी अमृत के समान लगता है। और जब मन अशांत होता है, तो सर्वोत्तम भोजन भी स्वादहीन लगता है।” उनका यह उत्तर केवल भोजन के संदर्भ में नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जीवन में सुख और संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि हमारे दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। यदि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाएँ, तो हमें हर क्षण में आनंद मिल सकता है। लेकिन यदि हम हमेशा अपेक्षाओं में उलझे रहें, तो कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते।

यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद सरलता में छिपा हुआ है। आज का मनुष्य भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है कि अधिक धन, अधिक संसाधन और अधिक वैभव उसे संतुष्टि देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि संतोष का संबंध बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से है। गुरुदेव के पास उस समय न तो कोई विशेष भोजन था और न ही कोई विलासिता, फिर भी वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। इसका कारण यह था कि उनका मन वर्तमान क्षण के साथ एकाकार हो गया था।

जब मनुष्य प्रकृति के निकट होता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन का सौंदर्य सरलता में है। एक साधारण पत्ता, एक साधारण भोजन, और एक साधारण क्षण भी हमें गहरी शांति दे सकता है, यदि हम उसे पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ अनुभव करें।

गुरुदेव का यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व होता है। हमें हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। उस यात्रा में हर मोड़, हर अनुभव, और हर क्षण हमें कुछ नया सिखाता है।

अंततः, सच्चा स्वाद भोजन में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में होता है। जब मन शांत, संतुष्ट और वर्तमान में स्थित होता है, तब साधारण से साधारण वस्तु भी दिव्य अनुभव बन जाती है। यही सच्ची अनुभूति है, यही जीवन का सार है, और यही वह रहस्य है जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन को पूर्णता और आनंद से भर सकता है।

खतरा बना एंटीबायोटिक का दुरुपयोग

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) आज दुनिया के सामने खड़े सबसे गंभीर, लेकिन सबसे कम समझे गए या जा रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। यह समस्या धीरे-धीरे उपचार के आधार को कमजोर कर रही है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जब दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, तब सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका असर और भी गहरा है, जहां संक्रमण का बोझ अधिक और स्वास्थ्य संसाधन सीमित हैं।

2019 में दुनिया भर में लगभग 50 लाख मौतें एएमआर से जुड़ी थीं। यदि वर्तमान में हम इसे लेकर जागरूक नहीं हुए और इस पर नियंत्रण नहीं किया, तो भविष्य में यह संख्या प्रतिवर्ष एक करोड़ तक पहुंच सकती है। यह संकट इसलिए भी खतरनाक है, क्योंकि इसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं, जब उपचार बेअसर होने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

प्रधानमंत्री मोदी यह कहते रहे हैं कि चिकित्सकीय परामर्श के बिना एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अपील इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम सर्दी-खांसी, बुखार या वायरल संक्रमण जैसे कई रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। इसके बावजूद दवाओं का अनावश्यक और तर्कहीन उपयोग हमारे समाज में आम व्यवहार बन चुका है। इस तरह का अंधाधुंध प्रयोग सूक्ष्म जीवों को और अधिक प्रतिरोधी बनने का अवसर देता है, जिससे भविष्य में जीवन रक्षक दवाएं असरहीन हो सकती हैं।

यह स्थिति इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि जिस गति से सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी बन रहे हैं, उस अनुपात में नई एंटीबायोटिक दवाएं विकसित नहीं हो रहीं। पिछले लगभग दो दशकों में एंटीबायोटिक्स की कोई नई प्रमुख श्रेणी सामने नहीं आई है। एक नई एंटीबायोटिक दवा विकसित करना 15 से 20 वर्षों का लंबा, जटिल और अत्यंत महंगा कार्य है। भारी निवेश के बावजूद आर्थिक प्रतिफल सीमित रहता है। यही कारण है कि फार्मास्युटिकल कंपनियां इस क्षेत्र में बड़े निवेश से कतराती हैं। सरकार ने एएमआर को रोकने के लिए कई स्तरों पर कार्ययोजना बनाई है। राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दवा प्रतिरोध के रुझानों पर समय रहते नजर रखी जा सके। एंटीबायोटिक की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर नियंत्रण, अस्पतालों में एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप कार्यक्रम और प्रयोगशाला आधारित जांच को बढ़ावा देना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन में एंटीबायोटिक के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास भी सरकार की वन हेल्थ रणनीति का हिस्सा हैं, जो मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा मानती है।

इस लड़ाई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अहम भूमिका में है। आइएमए देश भर के चिकित्सकों को एएमआर के प्रति जागरूक करने, जिम्मेदार प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ावा देने और आम जनता तक सही संदेश पहुंचाने में सक्रिय जिम्मेदारी निभा रहा है। आइएमए की एएमआर कमेटी लगातार यह चेतावनी देती रही है कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग केवल इलाज को मुश्किल नहीं बनाता, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए खतरा पैदा करता है। एंटीबायोटिक का सबसे अधिक दुरुपयोग मानव स्वास्थ्य की रक्षा के बजाय पशुओं, फल और सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाने में हो रहा है।

इस संकट का एक गंभीर पहलू पर्यावरण और नदियों से भी जुड़ा है। मानव गतिविधियों, अस्पतालों के अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे, फार्मों से बहकर आने वाले एंटीबायोटिक अवशेष और पशुओं के मल-मूत्र के कारण नदियां, तालाब और भूजल भी एएमआर से संक्रमित हो रहे हैं। कई नदियों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक अवशेष पाए जाने की चेतावनियां विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं। ये एएमआर का सक्रिय वाहक बनते जा रहे हैं, जो पानी, मिट्टी और खाद्य शृंखला के जरिये मानव तक यह खतरा पहुंचा रहा है। इससे भोजन श्रृंखला दूषित और जल स्रोत संक्रमित हो रहे हैं। सामान्य जल शोधन प्रणालियां एएमआर को छानने में सक्षम नहीं हैं, जिससे यह पानी के जरिये भी मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है। एएमआर के खिलाफ लड़ाई केवल डाक्टरों या सरकार की नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब तक आम नागरिक इस खतरे को नहीं समझेंगे, तब तक नीतियां और नियम सीमित असर ही दिखा पाएंगे। एंटीबायोटिक का उपयोग केवल योग्य चिकित्सकों की पर्ची पर होना चाहिए। दवाओं की पूरी खुराक और सही अवधि का पालन जरूरी है। ओवर-द-काउंटर बिक्री पर लगे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन होना चाहिए।

स्वच्छता, साफ-सफाई, सुरक्षित पानी और व्यापक टीकाकरण संक्रमण को रोकने के सबसे प्रभावी साधन हैं। बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाओं से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सही बीमारी में सही दवा दी जाए। साथ ही एंटीमाइक्रोबियल अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकारी निवेश और प्रोत्साहन बढ़ाना समय की मांग है। अंततः एएमआर केवल एक चिकित्सकीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत चुनौती है। आज एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदार उपयोग ही यह तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के पास इलाज के प्रभावी विकल्प बचेंगे या नहीं।

अभियान

रामनगरी अयोध्या की प्रथम यात्राः श्रीराम दर्शन से पहले जानने योग्य संपूर्ण अनुभव और तैयारी

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और हृदय भक्ति से भर उठता है। उन्हीं पवित्र स्थानों में सबसे प्रमुख है अयोध्या, जिसे मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक भगवान श्रीराम की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह नगरी केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जब कोई भक्त पहली बार अयोध्या पहुँचता है और भव्य राम मंदिर के दर्शन करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास का मिलन होता है।

अयोध्या की यात्रा की योजना बनाते समय सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यहाँ तक पहुँचने के कई सुविधाजनक और बजट अनुकूल विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आप देश की राजधानी दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर से यात्रा कर रहे हैं, तो रेल यात्रा सबसे किफायती और आरामदायक माध्यम माना जाता है। भारतीय रेल द्वारा अयोध्या और निकटवर्ती शहरों के लिए नियमित ट्रेन सेवाएँ उपलब्ध हैं। ट्रेन से यात्रा करने का एक विशेष लाभ यह है कि यह न केवल सस्ती होती है, बल्कि इसमें आराम और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। स्लीपर श्रेणी उन यात्रियों के लिए उपयुक्त होती है, जो कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं, जबकि एसी श्रेणियाँ अधिक सुविधा और आराम प्रदान करती हैं। यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर दिखाई देने वाले खेत, नदियाँ और गाँव भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक प्रस्तुत करते हैं, जो यात्रा को और भी आनंददायक बना देते हैं।

बस यात्रा भी अयोध्या पहुँचने का एक अच्छा विकल्प है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और विभिन्न निजी कंपनियाँ नियमित रूप से अयोध्या के लिए बस सेवाएँ संचालित करती हैं। नॉन एसी बसें बजट यात्रियों के लिए उपयुक्त होती हैं, जबकि एसी और वोल्वो बसें अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। बस से यात्रा करने का एक विशेष आकर्षण यह होता है कि यात्री सड़क मार्ग से गुजरते हुए विभिन्न शहरों और कस्बों की जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यदि आप अपने परिवार या मित्रों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो निजी कार से यात्रा करना भी एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। यह आपको अपनी गति और सुविधा के अनुसार यात्रा करने की स्वतंत्रता देता है और रास्ते में आने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर रुकने का अवसर भी प्रदान करता है।

अयोध्या पहुँचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र क्षण होता है श्रीराम मंदिर के दर्शन का। मंदिर परिसर अत्यंत भव्य और सुव्यवस्थित है, जहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने साथ केवल आवश्यक वस्तुएँ ही रखें। मोबाइल फोन, बड़े बैग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए इन्हें सुरक्षित स्थान पर जमा करना पड़ता है। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह और शाम दोनों समय व्यवस्था उपलब्ध होती है, और श्रद्धालु शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से भगवान के दर्शन कर सकते हैं।

जब भक्त मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुँचता है और श्रीराम के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है, तो उसका मन स्वतः ही भक्ति और भावनाओं से भर जाता है। यह अनुभव केवल आँखों से देखने का नहीं, बल्कि हृदय से महसूस करने का होता है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से प्रतीक्षित वह क्षण अंततः आ गया हो। इस क्षण में व्यक्ति अपने जीवन की सभी चिंताओं और परेशानियों को भूल जाता है और केवल भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है। यही वह शक्ति है, जो अयोध्या को एक साधारण शहर से एक दिव्य तीर्थस्थल बनाती है। राम मंदिर के दर्शन के बाद हनुमान गढ़ी जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्थान अयोध्या के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि हनुमानजी यहाँ निवास करते हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। भक्त यहाँ आकर हनुमानजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, वह इस प्रयास को सार्थक बना देता है।

अयोध्या की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती, जब तक श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी के तट पर न जाएँ। सरयू नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। शाम के समय सरयू तट पर होने वाली आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। जब सैकड़ों दीपक एक साथ जलते हैं और उनकी रोशनी नदी की लहरों पर झिलमिलाती है, तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। मंत्रों की ध्वनि और घंटियों की गूंज मन को एक अलग ही लोक में ले जाती है। अयोध्या में दशरथ महल का दर्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है, जहाँ राजा दशरथ निवास करते थे और जहाँ श्रीराम ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ का वातावरण भक्तों को रामायण काल की याद दिलाता है और उन्हें उस युग की महानता का अनुभव कराता है। इसके अलावा अयोध्या में कई अन्य छोटे-बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल भी हैं, जहाँ जाकर श्रद्धालु अपनी यात्रा को और अधिक पवित्र बना सकते हैं।

यात्रा को सहज और सुखद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप पहले से योजना बनाकर चलें। यात्रा के समय मौसम की जानकारी अवश्य रखें और उसी के अनुसार अपने कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएँ साथ रखें। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो सामान्य दिनों में यात्रा करना बेहतर होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे दर्शन में अधिक समय लग सकता है।

अयोध्या की यात्रा केवल एक स्थान पर जाने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है, तो वह केवल मंदिर के दर्शन नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर की शांति और विश्वास को भी खोजता है। यह यात्रा उसे यह एहसास कराती है कि जीवन का वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतोष में है।

अंततः, अयोध्या की यात्रा हर श्रद्धालु के जीवन का एक ऐसा अनुभव होती है, जो उसे हमेशा याद रहता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की भक्ति और यहाँ की ऊर्जा व्यक्ति के मन और आत्मा को एक नई शक्ति प्रदान करती है। जब भक्त श्रीराम के दर्शन करके लौटता है, तो उसके भीतर एक नई आशा, नई ऊर्जा और नया विश्वास जन्म लेता है। यही अयोध्या की महिमा है, और यही वह दिव्य अनुभव है, जो हर श्रद्धालु को जीवन भर प्रेरणा देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

ईद और विवाह सीजन की दस्तक से सूरत का टेक्सटाइल उद्योग फिर चमका, ऑर्डरों की बाढ़ से व्यापार में नई ऊर्जा

(जीएनएस)। दिवाली के बाद कई महीनों तक सुस्ती और अनिश्चितता का सामना कर रहे सूरत के टेक्सटाइल बाजार में अब एक बार फिर रौनक लौट आई है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही ईद और विवाह सीजन की आहट ने इस उद्योग में नई जान फूंक दी है। देशभर के विभिन्न राज्यों से अचानक बढ़े ऑर्डरों ने उत्पादन, परिवहन और व्यापार से जुड़े हर क्षेत्र में गतिविधियों को तेज़ कर दिया है। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के चेहरों पर अब संतोष और उम्मीद की झलक दिखाई दे रही है। बाजार में बढ़ती हलचल और लगातार हो रहे डिस्पैच इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि टेक्सटाइल उद्योग एक बार फिर अपनी पुरानी गति पकड़ रहा है।

करीब एक महीने पहले तक जहां सूरत से प्रतिदिन लगभग 150 ट्रक कपड़ा देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जा रहा था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 350 से 400 ट्रक प्रतिदिन तक पहुंच गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यह अचानक आई तेजी इस बात का प्रमाण है कि रिटेल बाजार में सूरत के कपड़े की मांग तेजी से बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों और लोडिंग पॉइंट्स पर दिन-रात गतिविधियां जारी हैं। ट्रक ड्राइवरों और मजदूरों को बिना रुके काम करना पड़ रहा है, ताकि समय पर माल देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जा सके। यह स्थिति केवल व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि यह पूरे औद्योगिक तंत्र के पुनर्जीवन का प्रतीक भी है।

व्यापारियों के अनुसार, ईद और शादी का सीजन एक साथ आने से साड़ियों, सूट, ड्रेस मटीरियल, लहंगे और अन्य पारंपरिक परिधानों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं। इन राज्यों में ईद और विवाह समारोहों के दौरान नए कपड़ों की खरीदारी की परंपरा होने के कारण सूरत के कपड़ों की मांग में हर साल वृद्धि होती है, लेकिन इस बार यह वृद्धि अपेक्षा से कहीं अधिक है। व्यापारियों का कहना है कि कई ग्राहकों ने पिछले साल की तुलना में इस बार दोगुना ऑर्डर दिया है, जिससे उत्पादन इकाइयों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

सूरत का टेक्सटाइल उद्योग देश के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादन केंद्रों में से एक माना जाता है। यहां पावरलूम, प्रोसेसिंग यूनिट, एम्ब्रॉयडरी यूनिट, डाइंग और प्रिंटिंग यूनिट सहित हजारों छोटे और बड़े उद्योग संचालित होते हैं। इन सभी इकाइयों का आपसी समन्वय ही इस उद्योग की ताकत है। जब ऑर्डर बढ़ते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे औद्योगिक तंत्र पर पड़ता है। मजदूरों को अधिक काम मिलता है, उत्पादन इकाइयों की मशीनें लगातार चलती रहती हैं और व्यापारियों की आय में वृद्धि होती है। वर्तमान में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिल रही है। टेक्सटाइल बाजार में आई इस तेजी का असर केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में काम की कमी के कारण कई मजदूर अपने गांव लौट गए थे या अन्य क्षेत्रों में काम करने लगे थे। अब जैसे-जैसे ऑर्डर बढ़ रहे हैं, उत्पादन इकाइयों में मजदूरों की मांग भी बढ़ गई है। कई फैक्ट्री मालिकों ने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर बुलाना शुरू कर दिया है और कुछ जगहों पर ओवरटाइम भी कराया जा रहा है। इससे मजदूरों की आय में वृद्धि हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इस समय अत्यधिक व्यस्त है। सीमित संसाधनों और वाहनों के कारण कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां नई बुकिंग लेने में असमर्थ हैं। कुछ बड़ी कंपनियों ने अस्थायी रूप से नई बुकिंग रोक दी है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बड़ी संख्या में ऑर्डर लंबित हैं। माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापारी अब वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों, छोटे मालवाहक वाहनों और यहां तक कि लग्जरी बसों के पार्सल सेक्शन का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि समय पर माल ग्राहकों तक पहुंच सके। यह स्थिति दर्शाती है कि बाजार में मांग कितनी अधिक है और व्यापारी उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अनुसार, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वार्षिक टर्नओवर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये है, जो इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों में से एक बनाता है। इस उद्योग की विशेषता यह है कि यह न केवल बड़े व्यापारियों, बल्कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए भी रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। दिसंबर से अप्रैल तक का समय इस उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में सालाना कारोबार का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। इस बार ईद और विवाह सीजन के कारण व्यापारियों को उम्मीद है कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कारोबार होगा और नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।

सूरत में 240 से अधिक टेक्सटाइल मार्केट और लगभग 70,000 से अधिक दुकानें संचालित हो रही हैं। रिंग रोड, सलाबतपुरा, कतारगाम और उधना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इन दिनों भारी भीड़ देखी जा सकती है। दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और व्यापारी नए-नए डिजाइनों के कपड़े बाजार में ला रहे हैं। आधुनिक फैशन ट्रेंड के अनुसार डिज़ाइन किए गए कपड़ों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। युवा वर्ग विशेष रूप से नए और आकर्षक डिजाइनों को पसंद कर रहा है, जिससे बाजार में विविधता और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस समय टेक्सटाइल उद्योग में तकनीक का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल प्रिंटिंग, ऑटोमेटेड मशीनों और ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम के माध्यम से उत्पादन और वितरण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया जा रहा है। कई व्यापारी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ऑर्डर ले रहे हैं, जिससे देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच बनाई जा रही है। इससे व्यापार का दायरा बढ़ रहा है और नए ग्राहकों को जोड़ने में मदद मिल रही है।

टेक्सटाइल उद्योग में आई इस तेजी का सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और पैकेजिंग जैसे सहायक क्षेत्रों में भी काम बढ़ गया है। इससे शहर की समग्र आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले महीनों में सूरत का टेक्सटाइल उद्योग और अधिक मजबूत होगा।

गुजरात का यह शहर लंबे समय से देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है और यहां उत्पादित कपड़े पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। सूरत की पहचान केवल उत्पादन की मात्रा से ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता और डिज़ाइन की विविधता से भी है। यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारी यहां से कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से भावनगर में 50 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण, प्रधानमंत्री ने असम से दिखाई हरी झंडी

पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत गुजरात को भेंट, आगामी समय में राज्य के 8 शहरों में 750 से अधिक ई-बसें चलेंगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को असम से 5450 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पीएम ई-बस सेवा योजना अंतर्गत भावनगर शहर में 50 ई-बसों को हरी झंडी दिखाई।

भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से स्वच्छ, विश्वसनीय तथा टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम ई-बस सेवा एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के प्रारंभिक चरण में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र (नागपुर), चंडीगढ़ तथा असम (गुवाहाटी) में भी बसें आवंटित की गई हैं। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) को

गुजरात के शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग की राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आगामी समय में राज्य के आठ शहरों में इस योजना के अंतर्गत 750 बसें चलाने का आयोजन किया गया है।

भावनगर गुजरात का प्रथम शहर है, जहाँ इस योजना अंतर्गत 50 बसों की भेंट दी गई है। भावनगर में कुल 100 बसों द्वारा नागरिकों के लिए परिवहन सुविधा अधिक सुदृढ़ बनाई जाएगी। ये बसें वातानुकूलित एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधा से सज्ज हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन बसों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। आगामी समय में राज्य में आठ शहरों में ई-बसें शुरू की जाएंगी; जिनमें वडोदरा में 250, राजकोट में 100, भावनगर में 100, गांधीनगर में 100, जामनगर में 50, जूनागढ में 50, गांधीधाम में 80 तथा नवसारी में 20 ई-बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तकनीकी सुविधाएँ विकसित करने में गुजरात अग्रणी भूमिका निभा रहा है। समग्र देश में एक एकीकृत प्रयास के हिस्से के रूप में यह पहल पर्यावरणानुकूल परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

महेसाणा-जगुदन सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के महेसाणा-जगुदन स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 974 एवं 975 के पुनर्निर्माण के संबंध में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो निम्नानुसार हैः-

पूर्णतः रद्द ट्रेन

दिनांक 17.02.2026 की ट्रेन संख्या 79435/79436 साबरमती-पाटन-साबरमती डेमू रद्द रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

दिनांक 16.02.2026 की 19032 योगनगरी ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

दिनांक 16.02.2026 की 19412 दौलतपुर चौक-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। यात्री ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।

गुजरात को मिली छठी वंदे भारत एक्सप्रेस,असारवा उदयपुर सिटी के बीच शुरू होगी यह प्रतिष्ठित ट्रेन सेवा

(जीएनएस)। भारतीय रेल द्वारा गुजरात में आधुनिक रेल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असारवा–उदयपुर सिटी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू की जा रही है। यह गुजरात की छठी वंदे भारत ट्रेन होगी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के साथ-साथ यात्री सुविधा, पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। भारतीय रेल अपग्रेड किए गए स्टेशनों, नई रेल लाइनों और अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। असारवा–उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस इसी प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है। यह अत्याधुनिक ट्रेन रिक्लाइनिंग एवं आरामदायक सीटों, स्लाइडिंग दरवाजों, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बायो-टॉयलेट, स्वचालित प्रवेश एवं निकास द्वार तथा सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह ट्रेन यात्रियों को विश्वस्तरीय आराम प्रदान करते हुए तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देगी।

उद्घाटक सेवा:

ट्रेन संख्या 09663 उदयपुर सिटी-असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस 16 फरवरी 2026 को उदयपुर सिटी से 12.25 बजे प्रस्थान करेगी तथा 17.15 बजे असारवा पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन जावर, डूंगरपुर और हिम्मतनगर स्टेशनों पर रुकेगी।

नियमित सेवा: (सप्ताह में 6 दिन मंगलवार को छोडकर)

ट्रेन संख्या 26964 असारवा-उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस 18 फरवरी 2026 से प्रतिदिन (मंगलवार को छोडकर) असारवा से 17.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा 22.00 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 26963 उदयपुर सिटी-असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस 18 फरवरी 2026 से प्रतिदिन (मंगलवार को छोडकर) उदयपुर सिटी से 06.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा 10.25 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, डूंगरपुर तथा जावर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव चेयर कार सहित कुल 8 कोच रहेंगे। ट्रेन सं. 26964 की बुकिंग 15 फरवरी 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से 'मारी राष्ट्र प्रथमनी कल्पना' पुस्तक का अनावरण

- 'राष्ट्र प्रथम' जीवन जीने की दिशा, केवल राजनीतिक विचार नहीं : मुख्यमंत्री
- राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य : मुख्यमंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से शनिवार को अहमदाबाद में नवभारत साहित्य मंदिर प्रकाशित तथा उदय माहुरकर लिखित पुस्तक 'मारी राष्ट्र प्रथमनी कल्पना' (मेरी राष्ट्र प्रथम की कल्पना) पुस्तक का अनावरण किया गया। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि भारत देश के नागरिकों को अपनी संस्कृति, परंपरा एवं मूल्यों के प्रति गौरव की भावना होना जरूरी है। उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान मातृभाषा में व्यक्त हुए गौरव के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी भाषा तथा संस्कृति ही राष्ट्रीय पहचान की मूल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि जीवन जीवन जीने की दिशा है। जीवमात्र में परमात्मा का अंश बसता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक मूल्यों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भागीदारी दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज एवं राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देने वाली विचारधारा द्वारा ही समृद्ध तथा सशक्त भारत का निर्माण संभव होता है। श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन का उल्लेख करते हुए देश की एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक विविधता में

एकरूपता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व में आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' देशप्रेम तथा सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी है। सोमनाथ का इतिहास केवल धार्मिक आस्था का नहीं, अपितु राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है।

इस कार्यक्रम में पूज्य श्री ज्ञानवत्सल स्वामी ने भी प्रासंगिक संबोधन किया। पुस्तक के लेखक उदय माहुरकर ने पुस्तक की विषयवस्तु के बारे में जानकारी देते हुए 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को जीवन में आत्मसात करने की अपील की।

कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री भरतभाई पंड्या, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा, विधायक, साहित्यकार तथा साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

सोना-चांदी के वायदा के भाव में परस्पर विरुद्ध चालः सोना वायदा 765 रुपये तेज, चांदी वायदा 7380 रुपये लुढ़का

- क्रूड ऑयल वायदा 60 रुपये फिसला : कमोडिटी वायदाओं में 275929 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1618962 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 208470 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39262 पॉइंट के स्तर परबुलडेक्स फ्यूचर्स 38070 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 6 से 12 फरवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 1894910.47 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 275929.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1618962.23 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 39262 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 43576.82 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 208470.65 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 149396 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160250 रुपये और नीचे में 149396 रुपये पर पहुंचकर, 152071 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 765 रुपये या 0.5 फीसदी बढ़कर 152836 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 535 रुपये या 0.43 फीसदी गिरकर 124977 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 40 रुपये या 0.26 फीसदी की मजबूती के साथ 15678 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा 148889 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 157879 रुपये और नीचे में 148000 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 372 रुपये या 0.25 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 150688 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 152401 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160350 रुपये और नीचे में 151532 रुपये पर पहुंचकर, 153847 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 184 रुपये या 0.12 फीसदी गिरकर 153663 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 234063 रुपये के भाव पर खूलकर, 269373 रुपये के उच्च और 229187 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 243815 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 7380 रुपये या 3.03 फीसदी की गिरावट के साथ 236435 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 8647 रुपये या 3.43 फीसदी घटकर 243324 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 8378 रुपये या 3.33 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 243467 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 34968.18 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 21.7 रुपये या 1.77 फीसदी औंधकर 1206.3 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 3.1 रुपये या 0.97 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 323.35 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 40 पैसे या 0.13 फीसदी बढ़कर 307.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा फरवरी वायदा 1.85 रुपये या 0.98 फीसदी की गिरावट के साथ सप्ताह के अंत में 187.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 32409.17 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5738 रुपये के भाव पर खूलकर, 5976 रुपये के उच्च और 5648 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 60 रुपये या 1.04 फीसदी लुढ़ककर 5686 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 58 रुपये या 1.01 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 5689 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 316.8 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 332.4 रुपये के उच्च और 278.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 317.3 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 23.1 रुपये या 7.28 फीसदी लुढ़ककर 294.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 22.6 रुपये या 7.13 फीसदी औंधकर 294.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 983.7 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 16.9 रुपये या 1.72 फीसदी गिरकर 966.6 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 118235.96 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 90234.69 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 28779.82 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2091.10 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 155.27 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3941.99 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 12037.49 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 20247.73 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7914 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 46625 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 15374 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 204049 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 29825 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6252 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 11110 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 32165 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 9990 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 14591 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 36702 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 39999 के उच्च और 36700 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 1789 पॉइंट बढ़कर 39262 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा की नई चेतना, सूरत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

(जीएनएस)। भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां व्यवसाय, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित हो चुकी हैं। ऐसे समय में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूरत में उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों को जागरूक करने के उद्देश्य से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर एक विशेष अवेयरनेस और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry द्वारा समृद्धि, नानपुरा स्थित सभागार में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योग जगत और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यह कार्यशाला ऐसे समय में आयोजित की गई जब भारत में डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन सेवाओं और डेटा संग्रहण की मात्रा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। डिजिटल माध्यमों के विस्तार के साथ-साथ व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग, डेटा चोरी और साइबर अपराध के मामलों में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचे के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डेटा के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करना है। इस कानून के लागू होने के बाद हर उद्योग, कंपनी और संगठन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह डेटा संरक्षण से संबंधित नियमों का पालन करे और अपने सिस्टम को सुरक्षित बनाए।

कार्यक्रम में डेटा सुरक्षा और साइबर कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विस्तार से इस कानून के विभिन्न पहलुओं को समझाया और इसके व्यावहारिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। S.R.A. लीगल के एसोसिएट पार्टनर कृष्ण अग्रवाल और स्पोर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सीनियर लीगल मैनेजर रितिका दास ने प्रतिभागियों को डेटा संरक्षण के कानूनी प्रावधानों, दायित्वों और अनुपालन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में डेटा एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन चुका है और इसकी सुरक्षा केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी भी है।

कार्यक्रम के दौरान चैंबर के मानद कोषाध्यक्ष सीए. मितेश मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार को नई गति दी है। आज अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संग्रहीत की जा रही है। ऐसे में डेटा सुरक्षा कानून का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा और डिजिटल प्रणाली में विश्वास बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

विशेषज्ञों ने कार्यशाला में पर्सनल डेटा की परिभाषा को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि कोई भी ऐसी जानकारी, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, पर्सनल डेटा के अंतर्गत आती है। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, बैंक विवरण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं। इस डेटा को सुरक्षित रखना उस संगठन की जिम्मेदारी होती है, जो इसे एकत्र करता है और प्रोसेस करता है। उन्होंने डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी और महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी जैसे कानूनी शब्दों की भी व्याख्या की और बताया कि डेटा फिड्यूशरी वह संगठन होता है, जो डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि बड़े बैंक, वित्तीय संस्थान और कॉर्पोरेट कंपनियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां लागू होती हैं, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा को संभालते हैं। ऐसे संगठनों को अपने डेटा सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाना, नियमित ऑडिट करना और डेटा सुरक्षा नीति को स्पष्ट रूप से लागू करना आवश्यक होता है। यदि कोई संगठन डेटा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों ने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। यह बोर्ड एक नियामक और प्रवर्तन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे डेटा सुरक्षा कानून के उल्लंघन की स्थिति में जांच करने और दंड लगाने का अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी संगठन डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करें और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा हो सके।

कार्यक्रम के दौरान कंपनियों को डेटा सुरक्षा के लिए व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रत्येक संगठन को स्पष्ट डेटा सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए और अपने कर्मचारियों को इसके बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना, डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करना और नियमित सुरक्षा परीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा, कंपनियों को केवल आवश्यक और प्रासंगिक डेटा ही एकत्र करना चाहिए और अनावश्यक डेटा संग्रह से बचना चाहिए।

रितिका दास ने कॉर्पोरेट स्तर पर डेटा गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि डेटा संग्रह और उपयोग की प्रक्रिया पारदर्शी और जिम्मेदार होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि किसी भी व्यक्ति की सहमति स्पष्ट, स्वैच्छिक और सूचित होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में पहले से टिक किए गए चेक बॉक्स के माध्यम से सहमति लेना उचित नहीं माना जाता। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने डेटा के उपयोग के बारे में निर्णय ले सके। उन्होंने यह भी बताया कि डेटा सुरक्षा केवल कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह कंपनियों की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। यदि किसी कंपनी का डेटा लीक होता है, तो इससे न केवल कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी कम हो जाता है। इसलिए कंपनियों को डेटा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए।

कार्यक्रम की रूपरेखा ग्रुप चेयरमैन दीपक कुमार सेठवाला द्वारा प्रस्तुत की गई, जबकि डॉ. अनिल सरावगी ने कार्यक्रम का संचालन किया और अंत में सभी प्रतिभागियों और विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में उपस्थित उद्यमियों और व्यापारियों ने विशेषज्ञों से अपने प्रश्न पूछे और डेटा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

इस कार्यशाला ने यह स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 न केवल नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है, बल्कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूरत में आयोजित यह कार्यशाला उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई, जिसने व्यवसायों को डेटा सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और उन्हें इस नए कानून के अनुपालन के लिए तैयार किया। इस प्रकार, यह कार्यक्रम डिजिटल युग में जिम्मेदार डेटा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिसने उद्यमियों और संगठनों को यह समझने में मदद की कि डेटा सुरक्षा केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि डिजिटल भविष्य की नींव है।

श्रद्धा और भक्ति का विराट संगम, सूरत में 27 फरवरी को निकलेगी श्री सांवरिया सेवा संघ की 15वीं विशाल निशान पदयात्रा

(जीएनएस)। धार्मिक आस्था, परंपरा और भक्ति के अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रहा सूरत शहर 27 फरवरी को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होगा, जब श्री सांवरिया सेवा संघ द्वारा 15वीं विशाल निशान पदयात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह पदयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की आस्था, समर्पण और सामूहिक भक्ति का जीवंत प्रतीक है, जिसमें बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों, आयु समूहों और समुदायों के लोग एक साथ शामिल होकर भक्ति की एकता और आध्यात्मिक समरसता का संदेश देते हैं।

आयोजकों के अनुसार यह विशाल पदयात्रा सुबह 8 बजे सिटीलाईट स्थित सूर्यप्रकाश सोसायटी, अग्रसेन गार्डन के पास से निशान पूजन के साथ प्रारंभ होगी। पदयात्रा की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना और धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। निशान पूजन इस यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें श्रद्धालु अपने निशान को बाबा श्याम के प्रति समर्पण और आस्था के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। यह परंपरा भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और समर्पण के संबंध को दर्शाती है। इस भव्य पदयात्रा में लगभग 1500 निशानों के साथ 2000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। सभी श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर बाबा श्याम के जयकारों के साथ यात्रा में भाग लेंगे, जिससे पूरे मार्ग में भक्ति और उत्साह का अद्भुत वातावरण बनेगा। श्रद्धालुओं के चेहरों पर आस्था की चमक और मन में भक्ति की भावना इस आयोजन को और भी विशेष बना देती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त करने का अवसर भी होती है।

पदयात्रा के दौरान विभिन्न आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। विभिन्न बग्घियों पर सजी बाबा श्याम और अन्य देवी-देवताओं की सुंदर और भव्य झांकियां धार्मिक संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत करेंगी। इन झांकियों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिससे वे श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना को और अधिक प्रबल बनाती हैं। इसके साथ ही हनुमान जी की जीवंत झांकी भी यात्रा के साथ चलेगी, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और आकर्षक होगी। हनुमान जी की झांकी शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक होती है, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है।

इस यात्रा की एक और विशेषता यह है कि इसमें लाइव बैंड की मधुर धुनें पूरे मार्ग में भक्ति का वातावरण बनाए रखेंगी। बैंड की धुनों पर बजने वाले भक्ति गीत और धार्मिक संगीत श्रद्धालुओं के मन को भावविभोर कर देंगे और पूरे वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग देंगे। यह संगीत न केवल यात्रा को जीवंत बनाता है, बल्कि श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति को भी बढ़ाता है।

पदयात्रा मार्ग में अणुव्रत द्वार सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जलपान और पुष्प वर्षा की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान और सेवा भावना को दर्शाती है। पुष्प वर्षा और स्वागत से श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ जाता है और वे अपने आप को सम्मानित और प्रेरित महसूस करते हैं।

यह पदयात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सहयोग का भी प्रतीक है। इस आयोजन में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो यात्रा को सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करते हैं। स्वयंसेवक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

सूरत में छोटे व्यापारियों की बढ़ती चिंता, बिज़नेस टैक्स समाप्त करने और बढ़ी फीस वापस लेने की मांग हुई तेज

(जीएनएस)। सूरत सहित पूरे गुजरात में छोटे व्यापारियों के बीच आर्थिक दबाव और प्रशासनिक शुल्कों के बढ़ते बोझ को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे और मध्यम व्यापार से जुड़े संगठनों ने सरकार से तत्काल राहत देने की मांग करते हुए बिज़नेस टैक्स समाप्त करने और हाल ही में बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में व्यापार करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है और यदि समय रहते सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो इसका सीधा असर राज्य की व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार पर पड़ेगा।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) गुजरात के चेयरमैन प्रमोद भगत ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले सात वर्षों से व्यापारी बिज़नेस टैक्स समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू की गई थी, तब व्यापारियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे टैक्स समाप्त कर एक सरल और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन गुजरात में अब भी कुछ ऐसे कर और शुल्क लागू हैं, जो छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारी पहले ही बाजार में प्रतिस्पर्धा, बढ़ती लागत, ऑनलाइन व्यापार के दबाव और बदलते आर्थिक माहौल जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त टैक्स और फीस उनके लिए व्यापार जारी रखना और भी कठिन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और उन्हें राहत देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन और सहयोग मिलेगा, तो राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रमोद भगत ने यह भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब व्यापारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उस समय व्यापारियों को राहत देने के लिए ज़कात कर समाप्त किया गया था, जिससे व्यापारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली थी। इसके अलावा वर्ष 2019 में छोटे व्यापारियों को क्लर्क के रेट से भी छूट प्रदान की गई थी, जिससे उन्हें प्रशासनिक शुल्कों में राहत मिली थी। इन फैसलों के कारण व्यापारियों में सरकार के प्रति विश्वास और सकारात्मक भावना विकसित हुई थी। व्यापारियों को उम्मीद है कि वर्तमान सरकार भी इसी प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रोफेशनल टैक्स समाप्त करने का निर्णय लेगी।

हाल ही में 9 फरवरी 2026 को वेट्स एंड मेजर्स विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन ने व्यापारियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत 1 मिलीग्राम से लेकर वेब्रिज तक सभी प्रकार के वेटिंग स्केल की वार्षिक नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गई है। व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला छोटे व्यापारियों के लिए अत्यंत कठिन साबित होगा, क्योंकि अधिकांश छोटे दुकानदार और कारोबारी अपने व्यापार में वेटिंग स्केल का उपयोग करते हैं।

वेलेंटाइन डे पर सूरत के श्री कृष्णाराज विद्यालय में भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल, मातृ-पितृ पूजन दिवस ने भावनाओं से भर दिया वातावरण

(जीएनएस)। पश्चिमी प्रभाव के दौर में जहां 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के रूप में मनाने की परंपरा तेजी से बढ़ रही है, वहीं सूरत के पांडेसरा स्थित श्री कृष्णाराज विद्यालय, छत्रपति शिवाजी नगर (बमरोली रोड) ने इस दिन को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के सम्मान के रूप में मनाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। विद्यालय में मातृ-पितृ पूजन दिवस का आयोजन बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और भावनात्मक वातावरण में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त कर भारतीय संस्कारों की जीवंत झलक प्रस्तुत की। इस आयोजन ने न केवल विद्यार्थियों बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के मन में भी गहरी भावनात्मक छाप छोड़ी और पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के अंग्रेजी माध्यम और नर्सरी से कक्षा 11 तक के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय परिसर में सुबह से ही एक विशेष वातावरण देखने को मिला, जहां विद्यार्थी पारंपरिक परिधान में सुसज्जित होकर अपने माता-पिता के स्वागत और पूजन के लिए तैयार थे। जैसे ही अभिभावक विद्यालय पहुंचे, उनका तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित कर और सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। इस दृश्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा का सजीव उदाहरण है।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की प्रार्थना और सरस्वती वंदना से हुआ, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिकता और श्रद्धा का संचार हुआ। विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता को भगवान के समान मानते हुए विधिवत तिलक, अक्षत और पुष्प अर्पित कर उनका पूजन किया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह क्षण अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था, जब छोटे-छोटे बच्चे अपने माता-पिता के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त कर रहे थे। कई अभिभावकों की आंखें इस दृश्य को देखकर भावुक हो गईं, क्योंकि उनके लिए यह अनुभव जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक था।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए अपने माता-पिता की परिक्रमा भी की। यह परंपरा उस पौराणिक प्रसंग से प्रेरित है, जिसमें गणेश जी ने अपने माता-पिता शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर उन्हें ही अपना संपूर्ण संसार माना था। इसी भाव को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता की परिक्रमा कर यह संदेश दिया कि माता-पिता ही उनके जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। यह दृश्य न केवल धार्मिक परंपरा का प्रतीक था, बल्कि यह विद्यार्थियों में संस्कार, सम्मान और कृतज्ञता की भावना को भी दर्शाता है।

जिन विद्यार्थियों के माता-पिता किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों को माता-पिता के समान मानकर उनकी पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह क्षण इस बात का प्रमाण था कि भारतीय संस्कृति में गुरु और शिक्षक को भी माता-पिता के समान सम्मान दिया जाता है। इस आयोजन ने विद्यार्थियों को यह सिखाया कि जीवन में माता-पिता और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है और उनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजेन्द्र कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में जहां भौतिकता और पाश्चात्य प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, वहां बच्चों में संस्कार, सम्मान और कृतज्ञता की भावना विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि माता-पिता का सम्मान करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि 14 फरवरी को मातृ-पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय सनातन संस्कृति की मूल भावना से जोड़ना है।

मतदाता सूची संशोधन में देरी ने खड़े किए सवाल, कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तय समयसीमा से पीछे

(जीएनएस)। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी और लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक होते हैं। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मतदाता सूची का संशोधन और अद्यतन किया जाता है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिल सके। इसी उद्देश्य से Election Commission of India द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चलाई जा रही है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अपेक्षित गति नहीं देखी गई और कई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित समयसीमा तक अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने में असफल रहे, जिससे चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक दक्षता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 फरवरी तक नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करनी थी, लेकिन अधिकांश राज्य इस समयसीमा का पालन नहीं कर सके। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक समन्वय की कमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि इतने बड़े स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं। हालांकि, इस बीच दो केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार वहां की अंतिम मतदाता सूची में कुल 9,44,211 मतदाता शामिल हैं, जबकि लक्षद्वीप में 57,607 मतदाताओं के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। यह दर्शाता है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर उचित समन्वय और समयबद्ध कार्यप्रणाली अपनाई जाए, तो इस प्रकार की जटिल प्रक्रिया को भी समय पर पूरा किया जा सकता है।

मतदाता सूची संशोधन की यह प्रक्रिया अत्यंत व्यापक और जटिल होती है, जिसमें करोड़ों लोगों के नामों का सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नामों को हटाना और अन्य आवश्यक सुधार शामिल होते हैं। इस बार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे इस संशोधन अभियान में लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो इस प्रक्रिया के विशाल पैमाने को दर्शाता है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की जानकारी को अद्यतन करना अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर सटीक समन्वय और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।

चुनाव आयोग के अनुसार कई राज्यों में निर्धारित कार्यक्रम का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने में देरी हुई। निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समय पर आवश्यक कार्य पूरा न कर पाना, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक बाधाएं और कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएं इस देरी के प्रमुख कारणों में शामिल रही हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विवादित मामलों के न्यायिक स्तर तक पहुंच जाने से भी प्रक्रिया प्रभावित हुई और कई मुद्दे Supreme Court of India तक पहुंचे, जिससे अंतिम सूची प्रकाशित करने में और अधिक समय लग गया।

इस देरी का प्रभाव कई प्रमुख राज्यों में स्पष्ट रूप से देखा गया है। राजस्थान को 7 फरवरी को अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी करनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसकी तिथि बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी अंतिम सूची प्रकाशित करने की समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। वहीं देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया और अधिक विलंबित हो गई है और वहां अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की नई तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। इन राज्यों में समयसीमा बढ़ाने का निर्णय यह दर्शाता है कि प्रशासन इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहता है।

मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की विश्वसनीयता का आधार होता है। यदि मतदाता सूची में त्रुटियां होती हैं, तो इससे योग्य नागरिकों का नाम छूट सकता है या अयोग्य व्यक्तियों का नाम सूची में शामिल रह सकता है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता से लेता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि अंतिम सूची पूरी तरह सटीक और विश्वसनीय हो। हालांकि, इस बार सामने आई देरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक और आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणाली का अधिक प्रभावी उपयोग करके इस प्रक्रिया को और अधिक तेज और सटीक बनाया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में आधार, जनगणना और अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके मतदाता सूची को अधिक तेजी से अद्यतन किया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने कार्य को अधिक कुशलता से पूरा कर सकें।

मतदाता सूची संशोधन में देरी का एक महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। कई बार राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को लेकर अपने-अपने हितों के अनुसार आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करते हैं, जिससे प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाती है। हालांकि, चुनाव आयोग का प्रयास हमेशा यह रहता है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करे और किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त रहकर निर्णय ले।

बोर्ड परीक्षार्थियों की एकाग्रता के लिए सख्त कदम, सूरत में रात 10 बजे के बाद DJ और तेज हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध

(जीएनएस)। गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों की पढ़ाई, मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए Surat Police ने एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है, जिसके तहत शहर में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, DJ और भारी वाहनों के तेज प्रेशर हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला विशेष रूप से उन हजारों विद्यार्थियों के हित में लिया गया है, जो आगामी दिनों में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिन्हें पढ़ाई के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है।

इस वर्ष Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होने जा रहे हैं। यह समय विद्यार्थियों के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें उनकी मेहनत, एकाग्रता और मानसिक संतुलन उनकी सफलता को निर्धारित करता है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार का शोर-शराबा, विशेष रूप से देर रात तक बजने वाला तेज म्यूजिक और भारी वाहनों के हॉर्न, उनकी पढ़ाई और नींद दोनों को प्रभावित करता है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए सूरत पुलिस ने यह कदम उठाया है, ताकि विद्यार्थियों को बिना किसी व्यवधान के अपनी तैयारी पूरी करने का अवसर मिल सके।

वर्तमान समय में सूरत शहर में विवाह समारोहों और सामाजिक आयोजनों का सीजन अपने चरम पर है। शहर के विभिन्न पार्टी प्लॉट, बैंक्वेट हॉल और खुले स्थानों पर देर रात तक DJ और लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, जिससे आसपास रहने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई अभिभावकों और विद्यार्थियों ने पुलिस से शिकायत की थी कि तेज आवाज के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। नींद की कमी और मानसिक तनाव का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर पड़ता है, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित होती है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने यह सख्त अधिसूचना जारी की है।

जारी आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्टी प्लॉट, बैंक्वेट हॉल या अन्य आयोजन स्थल पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति या आयोजनकर्ता इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस न केवल संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करेगी, बल्कि DJ सिस्टम, लाउडस्पीकर और अन्य उपकरणों को भी जब्त कर सकती है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि नियमों का सख्ती से पालन हो और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा, पुलिस ने भारी वाहनों द्वारा बजाए जाने वाले प्रेशर हॉर्न पर भी विशेष ध्यान दिया है। कई बार रात के समय सड़कों पर चलने वाले बड़े ट्रक और लग्जरी बसें अत्यधिक तेज हॉर्न बजाती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों, स्कूलों के आसपास और हाईवे से सटे क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके।

ध्वनि प्रदूषण केवल पढ़ाई में बाधा नहीं डालता, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अत्यधिक शोर से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और नींद की समस्या जैसी कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त नींद और शांत वातावरण अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उनकी याददाश्त और एकाग्रता बेहतर होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हो चुका है कि शांत वातावरण में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि शोर-शराबे के बीच पढ़ाई करने से उनकी उत्पादकता और मानसिक संतुलन प्रभावित होता है।

सूरत पुलिस का यह कदम केवल नियम लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को भी दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके।

इस निर्णय का अभिभावकों और विद्यार्थियों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है। कई अभिभावकों ने पुलिस के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और वे बिना किसी तनाव के अपनी तैयारी कर सकेंगे। उनका मानना है कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया है और इससे उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।